

तैयारी

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में यूपी स्टेट कैपिटल रीजन की 29 परियोजनाओं पर मंथन, एलडीए ने दिया प्रस्तुतिकरण

राज्य राजधानी क्षेत्र 26 हजार वर्ग किलोमीटर में बसेगा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राजधानी और आसपास के जिलों को एकीकृत विकास मॉडल से जोड़ने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। बुधवार को लोक भवन में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन (यूपीएससीआर) की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली को मिलाकर लगभग 26 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस रीजन के लिए 29 बड़ी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। बैठक में एलडीए के



06 शहरों में विकसित होंगी विकास माडल की परियोजनाएं

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि पूरे क्षेत्र के लिए जीआईएस आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार की जा रही है।

परियोजना में विस्तारित मेट्रो नेटवर्क को भी शामिल किया

राजधानी क्षेत्र में माल और परिवहन को नई गति मिलेगी

लॉजिस्टिक पार्क और फूड पार्क से बड़े निवेश



बैठक में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली परियोजनाओं पर भी विशेष फोकस रहा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक पार्क, फूड पार्क और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे आधारित कॉरिडोर ओरिएंटेड डेवलपमेंट जैसी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, उद्योगों को आधुनिक ढांचा उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

बदल जाएगी कनेक्टिविटी: यूपीएससीआर के तहत सबसे अधिक जोर परिवहन और कनेक्टिविटी नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर दिया गया है। इसके अंतर्गत

“राज्य राजधानी माला” के रूप में रीजनल रोड नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिससे छह जिलों के बीच तेज आवागमन संभव हो सकेगा।

गांवों तक पहुंचेंगी शहरी सुविधाएं, रुकेगा पलायन



मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने बैठक में निर्देश दिए कि चिन्हित सभी परियोजनाओं पर संबंधित विभागों से जल्द अभिमत प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन बनने से न केवल निवेश और व्यवसाय बढ़ेंगे, बल्कि गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। हाईस्पीड कनेक्टिविटी विकसित होने से लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे बड़े शहरों की ओर पलायन भी कम होगा।